जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 29 प्रभात चूरू, गुरूवार 28 मई, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वेणुगोपाल ने कर्नाटक पर जानबूझकर प्रैस को भ्रमित किया था

बेंगलुरु में अलग ही नज़ारा दिखा। मु.मंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट को ब्रेकफास्ट दावत दी और राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा, शायद इस्तीफा देने के लिए

- जानकार सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन सन्निकट है, उन्होंने इसके दो पहलू बताए।
- पहला तो यह कि सिद्धारमैया गुरुवार या शुक्रवार तक त्याग पत्र दे देंगे और फिर शुक्रवार या शनिवार को डीके शिवकुमार शपथ ले लेंगे।
- दूसरा यह कि अगर सिद्धारमैया कुछ वक्त लेते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा चुनाव के बाद होगा।
- सत्ता छोड़ने के एवज में सिद्धारमैया को राज्यसभा सीट, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बड़ी भूमिका और शिवकुमार की सरकार में उनके समर्थकों को मंत्री पद दिए जाने की पेशकश की गई है, सिद्धारमैया ने इस पर सोचने का समय मांगा है। हालांकि माना जा रहा है कि सिद्धारमैया मान गए हैं।

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 27 मई। पिछले हफ्ते जब डीके शिवकुमार से उनकी पदोन्नति की चर्चाओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, "अच्छा समय आएगा।" अब, कर्नाटक में बड़े राजनीतिक बदलाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और लगता है कि उनका समय सचमुच आ गया है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शीर्ष पद सौंपने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है - कब?

सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को दिल्ली में चली लंबी बैठकों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद छोड़कर डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपने के लिए राजी कर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो किसी भी बदलाव से इनकार कर मीडिया को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन बेंगलुरु की गतिविधियां कुछ और ही संकेत दे रही हैं। सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल के लिए नाश्ते का आयोजन किया है और राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है, संभवतः इस्तीफा सौंपने के लिए।

मामले की जानकारी रखने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की गिरफ्तारी, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

- जोशी के पुत्र ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा था कि लिखित रूप में कारण बताये बिना महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, 27 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाला से जुड़े केस में बिना आधार बताए तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने से जुड़े मामले में गृह विभाग और एसीबी के डीजी से जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की फिटनैस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी

मैमोरियल डे कार्यक्रम के दौरान ट्रंप लड़खड़ाते हुए दिखे, इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है

- ट्रंप समर्थकों ने फिटनैस संबंधी सवालों को खारिज कर दिया और कहा कि लंबे समय तक खड़े होने के कारण ऐसा हुआ है।
- लेकिन ट्रंप का लड़खड़ाने वाला वीडियों लाखों बार देखा जा चुका है और शेयर किया जा चुका है और अमेरिका के चुनावी माहौल में इसे लेकर बहस छिड़ गई है।

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 27 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक बार फिर ऑनलाइन बहस का केन्द्र बन गए हैं। "मेमोरियल डे" कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे समारोह के दौरान खडे लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से साझा किए गए इस वीडियो में ट्रंप को कार्यक्रम के दौरान फहराते हुए झंडों के बीच थोड़ा हिलते- डुलते और लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन आलोचकों ने राष्ट्रपति के स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने दावा किया कि सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वे अस्थिर दिख रहे थे।

हालांकि ट्रंप समर्थकों ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। कई लोगों का कहना था कि यह बहुत मामूली हरकत थी और संभवतः लंबे समय तक खुले मैदान में खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ।

मेमोरियल डे कार्यक्रम उन अमेरिकी सैनिकों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण गंवाए। ट्रंप इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ शामिल हुए, जहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई।

यह वीडियो अब तक ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है, जिससे अमेरिकी चुनाव के मौसम से पहले ट्रंप को लेकर चल रही राजनीतिक जांच और बहस और तेज हो गई है। हाल के वर्षों में अमेरिका में राजनीतिक नेताओं के स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके व्यवहार को लेकर ऐसी बहसें अक्सर वायरल होती रही हैं।

ट्रंप या वाइट हाउस की ओर से इस वीडियो को लेकर उठ रही अटकलों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

शांति समझौते के लिए ईरान ने कठोर शर्तें लगाईं

संभावना है कि अमेरिका इन शर्तों को शायद स्वीकार नहीं करेगा

- ईरान की पहली शर्त है, ईरान को आर्थिक राहत दी जाए, प्रतिबंधों में ढील दी जाए और विदेशों में फ्रीज संपत्ति छोड़ी जाए।
- ईरान की दूसरी शर्त है, खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य दबाव कम किया जाए। इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट के पास से नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील भविष्य में अमेरिकी हमलों के खिलाफ आश्वासन भी शामिल है।
- इसके अलावा ईरान अपना यूरेनियम भंडार भी पूरी तरह सौंपना नहीं चाहता। ईरान कुछ स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानता है।

- सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 27 मई। ईरान, वॉशिंगटन के साथ चल रही बेहद अहम बातचीत में दो ऐसी मांगें लेकर उतरा है, जिन पर वह किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है।

पहली मांग यह है कि ईरान को आर्थिक राहत दी जाए। इसके तहत प्रतिबंधों में ढील, वैश्विक तेल बाजारों तक फिर से पहुंच और विदेशों में जमा अपनी अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्ति की रिहाई चाहता है। माना जा रहा है कि ईरानी अधिकारी पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रोके गए लगभग 100 अरब डॉलर में से कम से कम कुछ हिस्से तक पहुंच चाहते हैं।

दूसरी मांग यह है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य दबाव कम किया जाए। इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील और भविष्य में अमेरिकी सैन्य हमलों के खिलाफ आश्वासन शामिल हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत में ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिनमें होर्मुज़ स्ट्रेट से बिना रोक-टोक व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बहाल करने के बदले, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करने की बात शामिल है।

एक और बड़ा विवाद का मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। तेहरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सौंपने की मांग का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि उसकी परमाणु गतिविधियां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं। ईरानी वार्ताकार चाहते हैं कि किसी भी समझौते में देश के भीतर कुछ स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनी रहे, क्योंकि वह इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानता है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इन शर्तों को स्वीकार करेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि वे किसी बड़े शांति समझौते के बजाय सीमित और व्यावहारिक समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील, ईरान के फ्रीज़ किए गए फंड की आंशिक रिहाई और सैन्य तनाव कम करने पर विचार कर सकते हैं, यदि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी दे और अपने परमाणु ठिकानों की कड़ी निगरानी के लिए राजी हो जाए।

तथापि, दोनों पक्षों के सामने बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक मजबूरियाँ है। ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि यदि ईरान किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। वहीं, प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता और इज़रायल समर्थक समूह किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा कोई भी समझौता अधिकतम दबाव की नीति को कमजोर करेगा। दूसरी ओर, अमेरिका, ईरान की परमाणु क्षमता पर कहीं ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाने की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके लिए तेहरान अभी तैयार नहीं है।

ऐसे में फिलहाल सबसे संभावित नतीजा कोई व्यापक शांति समझौता नहीं, बल्कि सीमित लेन-देन आधारित समझ हो सकती है। इसके तहत, ईरान खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम कर सकता है और जहाजों की आवाजाही बहाल कर सकता है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में सीमित राहत और कुछ आर्थिक रियायतें दे सकता है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नेतृत्व अपने देश में राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई नहीं देना चाहता। यही कारण है कि समय-समय पर सैन्य टकराव और तीखी बयानबाजी जारी रहने के बावजूद बातचीत भी साथ-साथ चल रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को एक और राहत मिली

राजश्री पान मसाले के विज्ञापन को लेकर जिला उपभोक्ता मंच द्वारा सलमान खान की उपस्थिति और हस्ताक्षर मिलान के आदेश पर अदालत ने रोक लगाई

- हालांकि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई यह रोक इस प्रकरण की अगली सुनवाई तक ही रहेगी, जो कि 6 जून को तय की गई है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुडे मामले में जिला उपभोक्त मंच, कोटा के 6 जनवरी के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि सलमान खान स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित हों। साथ ही अपने कोई ऐसे दस्तावेज साथ लेकर आएं, जिसमें उनके हस्ताक्षर से मिलान किया जा सकें। क्योंकि इस प्रकरण में सलमान की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में किए गए हस्ताक्षरों पर भी संदेह जताया जा रहा है। जिला उपभोक्ता मंच ने सलमान खान के हस्ताक्षर की एफ.एस.एल. जांच करवाने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने बुधवार को यह आदेश सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई यह रोक इस प्रकरण की अगली सुनवाई तक ही रहेगी, जो कि 6 जून को तय की गई है। इस मामले में सलमान की ओर से अधिवक्ता शिवांशु नवल और वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा व उनके सहायक अधिवक्ता योगेश कल्ला पैरवी के लिए पेश हुए थे।

ज्ञात रहे कि जिला उपभोक्ता आयोग में 12 दिसंबर 2025 को योगेन्द्र सिंह द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि राजश्री पान मसाला और सलमान खान तंबाकु के प्रयोग को लेकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता मंच ने 6 जनवरी 2026 को विज्ञापन पर रोक लगायी थी और यह आदेश कंपनी और सलमान खान का पक्ष सुने बिना ही दे दिए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी पर यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक कि वह अपना जवाब पेश नहीं कर देती। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को जब कंपनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने 6 जनवरी के आदेश को नहीं हटाया, उल्टा सलमान खान के हस्ताक्षरित शपथ पत्र में हस्ताक्षर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायत निकाय चुनाव में संयम लोढा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाई

- केविएट में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो प्रार्थी की सुने बिना आदेश नहीं दें।

जयपुर, 27 मई। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से दिए गए फैसले के संबंध में पूर्व विधायक संयम लोढा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की गई है। इसमें कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को यदि राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो कोई भी आदेश देने से पहले प्रार्थी का पक्ष भी सुना जाए और उसके बाद ही कोई आदेश दिया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन दिन आँधी-बारिश का अलर्ट

- मौसम विभाग ने राजस्थान में 28 से 30 मई तक आँधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है, इससे गर्मी में राहत मिल सकती है।

नई दिल्ली, 27 मई। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में 28 मई से आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है।

राजस्थान में 28, 29 और 30 मई को बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि धूल भरी आंधी कई जगहों पर बवंडर का रूप भी ले सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

पाक की दुविधा, ट्रंप की मानी तो जनता नाराज़ होगी, न मानी तो जो पाया वो गंवाना पड़ेगा

असल में ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते में 6 मुस्लिम देशों द्वारा अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकार करने की शर्त जोड़ दी है, यानि उन्हें इज़रायल से संबंध सामान्य करने होंगे।

- ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आठ देशों का उल्लेख किया है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, लेकिन पहले तीन देशों का ही विशेष महत्व है। बहरीन व यूएई इस समझौते पर साइन कर चुके हैं तथा टर्की, मिस्र, जॉर्डन के इज़रायल से कूटनीतिक संबंध हैं।
- हालांकि, ट्रंप ने पाकिस्तान को हस्ताक्षर से छूट की राहत दी, पर, उनकी पोस्ट में यह भी कहा कि अगर कोई देश अब्राहम अकॉर्ड पर साईन नहीं करता है तो उसे ईरान डील का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- बस इसी बात ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है, पाकिस्तान ने हालांकि पुराना रुख दोहराया, कि, कायदे आज़म जिन्ना ने इज़रायल को मान्यता नहीं देने का प्रावधान किया था पर, उसे डर है कि हाल ही में अमेरिका की मेहरबानी से मिडिल ईस्ट में उसने जो साख बनाई है, वह कहीं छिन ना जाए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट ने 6 मुस्लिम देशों में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में उन्होंने ईरान के साथ शांति समझौते को छह मुस्लिम देशों द्वारा "अनिवार्य" और "एक साथ" अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से जोड़ा है। इन देशों में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान शामिल हैं।

अब्राहम समझौते इज़रायल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की श्रृंखला हैं। ये समझौते मिडिल ईस्ट में व्यापार, कूटनीति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने करवाए थे। इनका नाम पैगम्बर इब्राहिम के नाम पर रखा गया, जिन्हें मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सभी मानते हैं। सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में मोरक्को, सूडान, जॉर्डन भी इसमें शामिल हो गए थे।

पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार सुशांत सरीन का कहना है कि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा कि मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नई मांग पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाए। यह भी साफ नहीं है कि ट्रंप ने यह बात सिर्फ यूं ही कही है या वे वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

फिर भी, ट्रंप ने शर्तें बदलकर क्षेत्रीय देशों के सामने गंभीर दुविधा खड़ी कर दी है। अगर वे अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, तो वे न केवल ट्रंप के गुस्से को न्योता देंगे, बल्कि क्षेत्र की पहले से तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति के और बिगड़ने का खतरा भी रहेगा। दूसरी ओर, अगर वे ट्रंप के दबाव के आगे झुकते हैं, तो उन्हें अपने देशों में आंतरिक अशांति और जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

अपनी पोस्ट में ट्रंप ने आठ देशों का उल्लेख किया- सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और यूएई। लेकिन अब्राहम समझौते के नजरिए से इनमें केवल पहले तीन देशों का ही विशेष महत्व है।

बहरीन और यूएई पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध हैं। ट्रंप ने कहा, एक या दो देशों को तुरंत हस्ताक्षर न करने के लिए छूट दी जा सकती है, और उन्होंने "उदारता" दिखाते हुए कहा कि इसे स्वीकार किया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पेपर लीक में दो और गिरफ्तार

- लातूर के डॉ. मनोज शिरुरे और पुणे के तेजस हर्षद कुमार शाह की गिरफ्तारी से पकड़े गए लोगों की संख्या 13 हो गई है।

नई दिल्ली, 27 मई। सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के दौरान दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरुरे की तीन छात्रों की मदद करने में अहम भूमिका है। इनमें एक कोचिंग सेंटर के मालिक का बेटा भी है। उन्होंने आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने में इन छात्रों की मदद की।

सीबीआई ने तेजस हर्षदकुमार शाह को भी गिरफ्तार किया है। वह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर, डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (एपीएमए) में फिजिक्स का फैकल्टी है। जांच में खुलासा हुआ है कि उसे लीक हुए फिजिक्स के प्रश्न मनीषा हवलदार से मिले थे। मनीषा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीबीआई ने विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा कि पूरी कड़ी और साज़िश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली गई है।